मेरा मास्क आपकी रक्षा करता है,
सभी के लिए मास्क
आपका मास्क मेरी रक्षा करता है

सच कहने की ताकत
जालंधर ब्रीज
साप्ताहिक समाचार पत्र

कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णत: पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 23 DECEMBER TO 29 DECEMBER 2020 • VOLUME- 22 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
Low Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD
CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE
E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

आत्मनिर्भर भारत अभियान विश्व कल्याण का मार्ग, देश को कर रहा सशक्त : पीएम मोदी

शांतिनिकेतन (कोलकाता)/ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को विश्व कल्याण का मार्ग बताया और कहा कि यह भारत को सशक्त करने के साथ विश्व में समृद्धि लाने का भी अभियान है। पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी विश्वविद्यालय से निकला संदेश आज पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत आज 'अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस' के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में विश्व का नेतृत्व कर रहा है तो वह आज इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के सही मार्ग पर है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस समारोह के दौरान उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के 'राष्ट्रवाद' के चिंतन में मुखर थी। उन्होंने कहा, ''उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है, उससे विश्व को लाभ हो और जो दुनिया में अच्छा है, भारत उससे भी सीखे। आपके विश्वविद्यालय का नाम ही देखिए, विश्व-भारती। मां भारती और विश्व के साथ समन्वय।'' उन्होंने कहा, ''विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान, भारत को सशक्त करने का अभियान है, भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है।'' रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित विश्व भारती, देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर पश्चिम बंगाल की प्रमुख हस्तियों में गिने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्ष 1951 में विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और उसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में शुमार किया गया था। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं।

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा-देश में नहीं है कोई लोकतंत्र

नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि देश में अब कोई लोकतंत्र नहीं रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आतंकवादी या राष्ट्रविरोधी करार दिया जाता है।

तीन कृषि कानूनों के संबंध में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे।

उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया, ''प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य है कि दो-चार बड़े पूंजीपतियों के लिए पैसा बनाया जाए। जो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा होता है उसे आतंकवादी बोल दिया जाता है। किसान खड़ा होता है तो उसे आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो उन्हें आतंकवादी बोलेंगे। जो इनसे सत्ता लेने की कोशिश करेगा उसको आतंकवादी

और राष्ट्र विरोधी बोला जाएगा।''

एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, ''भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है, देश में यह हकीकत में नहीं, केवल कल्पना में है।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''प्रधानमंत्री अक्षम व्यक्ति हैं जो तीन-चार लोगों की तरफ से इस व्यवस्था को चला रहे हैं।'' उन्होंने यह भी कहा कि 'आइडिया ऑफ इंडिया' पर हमला किया जा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस विरोध में खड़ी है। कांग्रेस नेता ने कहा, ''करोड़ों लोग हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं और यही लोग देश की रीढ़ हैं। हम मानते हैं कि कृषि क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। लेकिन अगर कृषि को तबाह कर दिया जाएगा तो करोड़ों लोगों को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा।'' उन्होंने बताया, ''राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये कानून किसान विरोधी हैं और इससे मजदूरों और किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है तथा किसान इन कानूनों के खिलाफ खड़ा है।''

गांधी ने कहा, ''प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मजदूर और किसान वापस चले जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक ये किसान पीछे नहीं हटेंगे।''

उन्होंने कहा, ''संयुक्त सत्र बुलाइए और कानूनों को वापस लीजिए।'' कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री ने कानून वापस नहीं लिए तो सिर्फ भाजपा और आरएसएस को नहीं, बल्कि देश को नुकसान होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दो करोड़ हस्ताक्षरों के साथ राष्टपति को ज्ञापन दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, ''भारत के किसान त्रासदी से बचने के लिए कृषि-विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा।''

कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की है उसके मुताबिक, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अनुबंध की खेती को लेकर कई किसानों ने खुद को भारी नुकसान होने की शिकायत की है और उनका यह भी कहना है कि हस्ताक्षर या मुहर के बिना ही अनुबंध किए गए।

साउथ अफ्रीका का कोरोना वायरस ब्रिटेन से भी ज्यादा खतरनाक, भारत आने के लिए बंद है विमान सेवा

नई दिल्ली/ब्यूरो

ब्रिटेन के न्यू कोविड-19 वैरिएंट को सामान्य कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक माना जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन के जिन इलाक़ों में ये पाया गया है वहां संक्रमण अपेक्षाकृत काफी अधिक फैल गया है। ब्रिटेन का ये करोना स्ट्रेन 8 अन्य देशों में भी फैल चुका है। लेकिन इनमें से साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां इस कोविड स्ट्रेन को ब्रिटेन वाले करोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक माना जा रहा है।

इस मामले में हम ख़ुशकिस्मत हैं। दरअसल, साउथ अफ्रीका के साथ फ्लाइट्स को लेकर भारत का कोई समझौता नहीं है यानी कोई एयर बबल स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए साउथ अफ्रीका से कोई फ्लाइट भारत नहीं आ रही है। मार्च के बाद से साउथ अफ्रीका से कोई फ्लाइट भारत नहीं आई है।

ब्रिटेन के न्यू कोविड स्ट्रेन से फैली दहशत के बीच डब्लूएचओ ने साफ किया है कि अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ब्रिटेन का कोविड स्ट्रेन बेकाबू या अधिक ख़तरनाक है। अभी तक ऐसा सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जिन इलाकों में फैला है वहां संक्रमण की दर ज़्यादा है।

अभी ये भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि साउथ अफ्रीका का कोविड वायरस ब्रिटेन से भी ज़्यादा खतरनाक है और न ही बात के कोई सबूत हैं कि साउथ अफ्रीका से ही ये ब्रिटेन पहुंचा है।

दरअसल जो उपाय हम करोना से लड़ने के लिए सामान्यत: करते आ रहे हैं उन्हीं उपायों को सख़्ती से बरतने की जरूरत है लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पांच दौर की वार्ता का नहीं निकला कोई नतीजा ! सरकार ने किसान यूनियनों को फिर किया आमंत्रित

नई दिल्ली/ब्यूरो

सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को वार्ता के लिए बृहस्पतिवार को फिर आमंत्रित किया, लेकिन स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित किसी भी नयी मांग को एजेंडे में शामिल करना ''तार्किक'' नहीं होगा, जिसका नए कृषि कानूनों से कोई संबंध नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने 40 किसान नेताओं को लिखे तीन पन्नों के पत्र में कहा, ''मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि सरकार प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए सभी मुद्दों पर खुले मन से और अच्छे इरादे से चर्चा करती रही है और ऐसा करती रहेगी। कृपया (अगले दौर की वार्ता के लिए) तारीख और समय बताएं।'' सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले पांच दौर की वार्ता का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक महीने से प्रदर्शन कर रहे किसान तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हैं। अग्रवाल ने किसान यूनियनों से कहा कि वे उन अन्य मुद्दों का भी ब्योरा दें जिनपर वे चर्चा करना चाहती हैं। वार्ता मंत्री स्तर पर नयी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर अग्रवाल ने कहा कि कृषि कानूनों का इससे कोई लेना-देना नहीं है और न ही इसका कृषि उत्पादों को तय दर पर खरीदने पर कोई असर पड़ेगा।

नैशनल हाईवे विभाग एन.एच.नंबर-44

नैशनल हाईवे विभाग जालंधर-फगवाड़ा मार्ग में बचे फोर लेन फ्लाईओवर और आर.ओ.बी. को भी करेगा आठ लेन

विभाग द्वारा कंसलटेंट कंपनी को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया

जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर ब्रीज द्वारा पिछले लंबे समय से नैशनल हाईवे विभाग को जालंधर फगवाड़ा मार्ग एन.एच. नंबर-44 पर जो त्रुटियाँ पाई गई है उन सबको एक एक करके अपने समाचार पत्र के माध्यम से उजागर किया गया और उन त्रुटियों को सही करने के लिए कई बार विभाग को पत्र भी लिखा गया और साथ में लोकल प्रशासन को भी नैशनल हाईवे विभाग के साथ अच्छे से ताल मेल बना कर इन कमियों को दूर करने के लिए कहा गया।

इसी के चलते नैशनल हाईवे विभाग द्वारा पीएपी फ्लाईओवर को फोर लेन से आठ लेन करने के लिए 32 करोड़ का टैंडर लगाया गया जिससे अभी जो लोगों को रामामंडी से घूम कर आना पड़ रहा है अब आठ लेन फ्लाईओवर बन जाने से

उन्हें घूम कर नहीं जाना पड़ेगा लेकिन जालंधर ब्रीज द्वारा नैशनल हाईवे विभाग से पत्र लिख कर पूछा गया की जब ट्रैफिक पीछे से आठ लेन से आएगा और आगे पहुँच कर जो फ्लाईओवर और आर.ओ.बी. फॉर लेन है अगर उन्हें भी आठ लेन नहीं किया गया तो एक्सीडेंट या गाड़ी खराब होने की स्थिति में वहां वाहन चालकों के लिए एक लेन ही बची रह जाएगी जिससे लोगों को घंटों तक लंबे जाम की स्थिति में फंसना पड़ सकता है और अब इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए विभाग द्वारा अपने जारी किए गए पत्र में लिखा गया है की विभाग एन.एच. नंबर-44 पर सारे फोर लेन फ्लाईओवर और आर.ओ.बी. को जालंधर- फगवाड़ा मार्ग में 8 लेन में तबदील करने के लिए विचार कर रहा है और इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए नैशनल हाईवे विभाग द्वारा कंसलटेंट कंपनी को सौंपने के लिया कहा जा चूका है और बाकी जितनी भी हाईवे में समस्याएं और कमियां पायी गयी हैं।

उनकी भी रिपोर्ट बना के जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहा गया है ताकि लोगों को अपने सफर दौरान किसी भी हादसे का शिकार न होना पड़े और किसी भी परिवार के रोटी कमाने वाले व्यक्ति को बचाया जा सके।

दखल

मंदी से उबरने की चुनौती

तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार को खर्च के मोर्चे पर ज्यादा उपाय करने होंगे। त्योहारी बिक्री से उपभोक्ताओं का मनोबल तो बढ़ा है, लेकिन अंतिम उपभोग व्यय पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अभी भी 11.3 फीसद कम है। रोजगार सृजन में तेजी आने, सभी मजदूरों और कामगारों के काम पर लौटने, कोरोना की दवाई या टीके के बाजार में आने से इसमें और भी तेजी आएगी।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ और सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन पहली तिमाही के 23.9 फीसद की तुलना में सुधर कर 7.5 फीसद रह गया। यह सुधार मौद्रिक नीति समिति के अनुमान शून्य से 9.8 फीसद कम और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान शून्य से 8.6 फीसद से बेहतर है। हालांकि, दूसरी तिमाही में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ, पर लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की वजह से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई, जिससे जीडीपी दर में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में गिरावट में कमी आई। पहली तिमाही में जीवीए शून्य से 22.8 फीसद कम रहा था, जो दूसरी तिमाही में घटता हुआ सात फीसद पर आ गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि लॉकडाउन के नकारात्मक असर से मुक्ति मिल रही है। जीडीपी का आकलन हर तिमाही में किया जाता है और साल के अंत में पूरे साल के जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं, वहीं जीवीए से अर्थव्यवस्था में होने वाले परिणाम और आय का पता चलता है।

जीवीए से इस बात का सूचक है कि तय अवधि में व्यय और कच्चे माल की कीमत को अलग करने के बाद कितने रुपए के सामान और सेवा का उत्पादन हुआ। इससे यह भी पता चलता है कि किस क्षेत्र, उद्योग या क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ। अर्थव्यवस्था में सुधार कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से आया है। कृषि क्षेत्र में दूसरी तिमाही में 3.4 फीसद की दर से वृद्धि हुई। पहली तिमाही में भी इस क्षेत्र में इसी दर से वृद्धि हुई थी। सबसे ज्यादा सुधार उद्योग क्षेत्र में दर्ज किया गया। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इस क्षेत्र में सिर्फ 2.1 फीसद की गिरावट आई, जबकि पहली तिमाही में 38.1 फीसद की गिरावट दर्ज की गई थी। निर्माण क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई। पूर्व के आंकड़ों से पता चलता है कि निर्माण क्षेत्र में वृद्धि पहली तिमाही से दूसरी तिमाही में हमेशा कम रहती है, लेकिन कोरोना काल में दूसरी तिमाही में पहली तिमाही से बेहतर परिणाम रहे हैं। इस अवधि में निर्माण क्षेत्र में वृद्धि होना आश्चर्यजनक है, क्योंकि आमतौर पर मानसून में निर्माण कार्य बंद रहते हैं।

विनिर्माण क्षेत्र में पांच लाख 79 हजार 683 रुपए का जीवीए वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2019 के जीवीए से अधिक है। बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता वाली सेवाओं में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इससे यह उम्मीद बंदी है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में और सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें वृद्धि के संकेत बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। जैसे सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 11.4 फीसद की गिरावट दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में गिरावट शून्य से 20.6 फीसद नीचे थी। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार आदि क्षेत्रों में भी सुधार हुआ, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं। वित्तीय सेवा, बीमा, रक्षा आदि क्षेत्रों में भी गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र का आकार राशि में 17.19 लाख करोड़ रुपए का रहा, जबकि वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में राशि में इसका आकार 17.35 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र का राशि में आकार वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही से सिर्फ 15 हजार करोड़ रुपए कम रहा। सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार को अभी कई कदम उठाने की जरूरत है।

अर्थव्यवस्था में निजी खपत का पहलू बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरी तिमाही में निजी खपत में वृद्धि हुई। हालांकि, वर्ष दर वर्ष के आधार पर इस मोर्चे पर वृद्धि दर शून्य से 11.3 फीसद कम रही। सरकार द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत खर्च में वृद्धि दर शून्य से नीचे 22.2 फीसद रही। हालांकि निजी उपभोग वित्त वर्ष 2020 की समान अवधि के मुकाबले सिर्फ दो सौ अंक कम है। कच्चे तेल की कीमत के नरम रहने से आयात लगातार संकुचन की स्थिति में है। निर्यात में सुधार हुआ है, लेकिन सुधार की गति ज्यादा तेज नहीं है। इसलिए व्यापार घाटे पर कोई खास सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर के लिए क्षेत्रवार ऋण वृद्धि का आंकड़े जारी किए हैं। इनके अनुसार उद्योग को छोड़ कर अन्य सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि दर में इजाफा हुआ है। हालांकि यह वृद्धि पिछले साल के सितंबर महीने से कम है, लेकिन तालाबंदी के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए इन आंकड़ों को उत्साहजनक माना जा सकता है।

सबसे अधिक ऋण वृद्धि वैयक्तिक ऋण क्षेत्र में दर्ज की गई है। अक्टूबर में घर, वाहन और दूसरे वैयक्तिक ऋण की भी मांग बढ़ रही है। कोरोना काल में कारपोरेट कंपनियां अपने खर्च को कम करने पर भी विशेष जोर दे रही हैं। सीमेंट और उपभोक्ता वस्तु आदि क्षेत्रों में कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में छह फीसद तक की कटौती की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2020 में कर्मचारियों के खर्च में पांच फीसद की कटौती की गई थी। छोटी कंपनियां, जिनका कारोबार पांच सौ करोड़ रुपए या उससे कम है, अपने खर्च में आक्रामक तरीके से कटौती कर रही हैं। इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में पच्चीस फीसद तक की कटौती की हैं। उदाहरण के तौर पर 1800 छोटी कंपनियां, जिनका कारोबार 50 करोड़ तक है ने अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में औसतन 11.5 फीसद की कटौती की है। जीडीपी के साथ-साथ सरकार ने वित्तीय आंकड़ों को भी जारी कर दिया है। राजकोषीय घाटा अक्टूबर 2020 के बजटीय अनुमान का 119.7 फीसद है। कुल प्राप्तियां बजटीय अनुमान का लगभग इकतीस फीसद है। सरकार द्वारा एकत्र किया गया राजस्व संग्रह 5.75 लाख करोड़ रुपए रहा। गैर-कर राजस्व, जिसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सीजीएसटी आदि कर राजस्व शामिल हैं, 1.16 लाख करोड़ रुपए रहा। यह बजटीय अनुमान का 30.2 फीसद है और अक्तूबर में इसमें पूर्व के महीनों की तुलना में वृद्धि हुई है। लेकिन विनिवेश से अब तक केवल 6,178 करोड़ रुपए मिल पाए हैं जो बजट अनुमान 1.20 लाख करोड़ रुपए बहुत कम हैं। सरकार ने अक्टूबर महीने में डेढ़ लाख करोड़ रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किया है, जो वित्त वर्ष 2020 की समान अवधि में 2.0 लाख करोड़ रुपए रहा था।

आंकड़े बताते हैं कि कोरोना से उत्पन्न आर्थिक दुष्परिणाम कम होने लगे हैं। जीडीपी में सुधार आना इसी बात का संकेत है। दूसरी तिमाही में निवेश उम्मीद से बेहतर रहा है, लेकिन निजी खर्च में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है। दूसरी तिमाही में सरकार द्वारा भी अपेक्षित खर्च नहीं किया जा सका है। तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार को खर्च के मोर्चे पर ज्यादा उपाय करने होंगे। त्योहारी बिक्री से उपभोक्ताओं का मनोबल तो बढ़ा है, लेकिन अंतिम उपभोग व्यय पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अभी भी 11.3 फीसद कम है। रोजगार सृजन में तेजी आने, सभी मजदूरों और कामगारों के काम पर लौटने, कोरोना की दवाई या टीके के बाजार में आने से इसमें और भी तेजी आएगी। समग्रता में दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि को पंख लगे हैं, जिसे और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उम्मीद की जा सकती है कि तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में और भी तेजी आएगी और विकास दर सकारात्मक होगी और अर्थव्यवस्था रफ्तार भरेगी।

विचार

डीडीसी के नतीजों से गदगद भाजपा

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हुए पहले डीडीसी चुनाव में में भाजपा 74 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका सीधा आशय है कि में भाजपा की ओर से विकास के मोर्चे पर किए गए प्रयासों पर भी मुहर लगी है।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हुए पहले डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिली। डीडीसी चुनाव में भाजपा 74 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। डीडीसी चुनाव में भाजपा को श्रीनगर, बांदीपोरा और पुलवामा जैसे इलाकों में जीत मिली है, जहां घाटी की पार्टियों का वर्चस्व माना जाता है। वहीं, एनसीपी को इस चुनाव में 67 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। दूसरी तरफ, पीडीपी केवल 27 सीटें ही जीत पाई है। हालांकि, अगर कुल मिलाकर बात की जाए, तो जम्मू संभाग में भाजपा तो वहीं कश्मीर घाटी में गुपकार ने परचम लहराया। भाजपा ने पहली बार घाटी में कमल खिलाया है। चुनाव में कांग्रेस का पहले से बेहतर प्रदर्शन रहा, जबकि नवगठित जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी भी खाता खोलने में सफल रही। बड़ी तादाद में निर्दलियों ने जीत दर्ज की है।

देखा जाए तो पिछले छह साल की कोशिशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर का रंग डीडीसी चुनावों में सुर्ख होने में कामयाब रहा। कश्मीर ने पहली बार भगवा चोला ओढ़ा और पार्टी तीन सीटें जीतने में सफल रही। संख्या बल में तो यह गुपकार गठबंधन के मुकाबले काफी कम है, लेकिन खास बात यह है कि आतंक का गढ़ दक्षिणी कश्मीर हो या फिर उत्तरी कश्मीर या अलगाववादियों का गढ़ रहे मध्य कश्मीर, सभी जगह भगवा ब्रिगेड ने एक-एक सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिला विकास परिषद चुनाव में आतंक का गढ़ रहे दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा की काकपोरा सीट से मिन्हा लतीफा, श्रीनगर (मध्य कश्मीर) की खानमोह से इंजीनियर एजाज और बांदीपोरा (उत्तरी कश्मीर) की तुलैल सीट से एजाज अहमद खान सीट जीतने में कामयाब रहे। कश्मीर घाटी में भाजपा ने 140 में से 50 पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। घाटी में कमल खिलाने को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए पार्टी ने युद्धस्तर पर तैयारियां कीं। केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी गई।

भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 25 सीटें (23 फीसदी मत) हासिल की थीं, लेकिन कश्मीर में खाता नहीं खुला था। पहली बार भाजपा पीडीपी संग मिलकर सरकार बनाने में भी कामयाब हुई थीं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास शुरू किया। मोदी के सपने को साकार करने के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों ने तमाम विकास योजनाओं की शुरूआत की। युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया कराने की भी कोशिशें हुईं। विश्लेषकों का कहना है कि अब जाकर भाजपा की स्वीकार्यता कश्मीर में भी बनी है। डीडीसी चुनाव में कश्मीर में भाजपा ने नींव रखी है। जल्द ही वहां बड़ा महल बनने वाला है। अलगाववाद तथा आतंकवाद परस्त राजनीति के अंत की शुरूआत है। यह जम्हूरियत की जीत है। साथ ही 30 साल के आतंक पर भी जीत है।

नए कानूनों से किसान होंगे खुशहाल

कृषि कानून किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग को सरल और सुगम बनाएंगे। यह विधेयक किसानों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बनेंगे। किसानों को समझना होगा कि सरकार जो काम करती है, उसमें समाज की भलाई छिपी होती है। किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं होता। अभी सरकार ने जो कानून बनाया है, वह किसानों को समृद्ध बनाने का काम करेगा। किसानों को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए।

अन्नदाताओं के जीवन में आसानी, समृद्धि, किसानी में आधुनिकता और प्रगति का मूल मंत्र लिए मोदी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसका लाभ देश के करोड़ों किसानों को लगातार मिल रहा है। नए कृषि कानूनों के आने से यह सुनिश्चित हो गया है कि किसान फसलों को चाहे मंडी में बेचें या फिर मंडी के बाहर, ये उनकी मर्जी होगी। अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वह बिना किसी अवरोध और रोक-टोक के वहां उपज बेच सकेगा। किसान पुत्र कृषिगत उद्योग धंधे अपने गांवों में ही लगा सकेंगे। किसान अब इन नवीन विधेयकों की बदौलत उद्योगपति भी बनेंगे। मोदी सरकार ने प्राथमिकता से स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप प्रगतिशील कदम उठाए है। देश के हर गांव का किसान फसलों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रहे इसलिए भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने, कोल्ड स्टोरेज बनाने और फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने के लिए सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए नए द्वार खोल दिए हैं।

यदि बात न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की करें, तो मोदी सरकार किसानों को बेहतर लागत मूल्य देकर किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल हुई है। वर्ष 2014 के पूर्व और वर्ष 2014 के बाद एमएसपी का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हम पायेंगे कि विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2014 के बाद निरंतर बढ़ा है। यूपीए सरकार में गेहूं का एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि आज 1975 रुपए प्रति क्विंटल है। मूंग दाल पर एमएसपी 4500 रुपए था, जबकि वर्तमान सरकार में 7200 रुपये है। मसूर दाल की एमएसपी 2950 रुपए से बढ़कर आज 5100 रुपए है। ज्वार 1520 रुपए से बढ़कर 2640 रुपए है। धान की एमएसपी 1310 रुपये से बढ़कर 1870 रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मध्यप्रदेश के किसानों से बात करते हुए इन उपलब्धियों का जिक्र भी किया और पूरी विनम्रता से अन्नदाताओं के हितों के लिए सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया।

किसान हितों के लिए दूरगामी व प्रभावकारी योजनाएं केंद्र सरकार लागू कर रही है। कृषि कानून किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग को सरल और सुगम बनाएंगे। यह विधेयक किसानों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बनेंगे। मध्यप्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं किसान है और वे किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। वे लगातार प्रदेश के किसानों से संवाद कर रहे है। ये कानून उनके हित में हैं। मैंने हरदा जिले में किसान चौपाल अभियान प्रारंभ किया है। नवीन कृषि कानूनों के समर्थन में किसान चौपालों में नए कृषि कानूनों पर मैं स्वयं बात कर रहा हूँ। हम सभी को मिलकर नउ कृषि कानूनों को लेकर किसानों से बातचीत करना चाहिए। इससे इन कानूनों को लेकर किसानों में फैले भ्रम को दूर किया जा सकेगा। सही मायनों में इन विधेयकों से किसानों की तकदीर और प्रदेश व देश की तस्वीर बदलेगी।

इन विधेयकों में वे तमाम प्रावधान किए गए हैं, जिनसे किसानों में खुशहाली आये और वे समृद्द हों। राष्ट्र में सुख और समृद्धि बढ़े। अंततः हम सबका लक्ष्य अपने राष्ट्र की खुशहाली है और सरकार लोक कल्याणकारी नीतियों से देश के करोड़ों लोगों के सपनों को साकार कर रही है। वर्ष 2014 के बाद मोदी सरकार की लोककल्याणकारी नीतियों से देश के किसानों के जीवन में बेहद सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसानों के बैंक खातों में रुपए छह हजार की राशि सीधे ट्रांसफर होती है। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत चार हजार रुपए की अतिरिक्त राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर कर रही है। यह क्रांतिकारी बदलाव है जिससे करोड़ों भोले-भाले किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में पूरे पैसे मिलना सुनिश्चित किया है। देश के हर किसान को पानी मिले और हर खेत तक पानी पहुंचे इस दिशा में मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने में जुटी है। साथ ही मधुमक्खी पालन,पशुपालन पालन और मछली पालन को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस साल पंचायती राज स्थापना दिवस 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के सरपंचों से बात करते हुए किसानों के जीवन में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की रूप में स्वर्णिम योजना की शुरुआत की थी। जिससे भारत के किसान, ग्रामीण समाज का विकास और प्रगति से सीधे जुडने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन से गांव, खेत और भूमि की मैपिंग की जा रही है। इससे गांवों में संपत्ति को लेकर विवाद खत्म हो जाएंगे। इससे भूमि की सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी। पहले गांव की जमीन पर लोन मिलना मुश्किल होता था,इसी कारण जोत की जमीन बेचकर किसान परिवार शहर की ओर पलायन कर जाते थे। अब गांवों में भी लोग बैंकों से लोन ले सकेंगे और इन सब सुविधाओं के कारण ग्रामों के विकास कार्यों को प्रगति मिलेगी। जमीन की मैपिंग के बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। ग्रामीणों के पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर ग्रामीण बैंक से लोन ले सकेंगे। नये विधेयकों के आने से किसान आगे बढ़कर उद्यमी बनेंगे। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे।

वास्तव में ये तीनों कानून इसलिए बनाए गए हैं कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। पहले देश के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए जरूरी था कि वे अपनी स्थानीय मंडियों में जाएं और आढ़तियों (दलालों) की मदद से अपना माल बेचें। अब उन पर से यह बंधन हट जाएगा। वे अपना माल सीधे बाजार में ले जाककिसानों के फायदे का कानून बेच सकते हैं। याने पूरा देश उनके लिए खुल गया है। अब वे स्थानीय मंडियों और आढ़तियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्हें न तो अब मंडी-टैक्स देना पड़ेगा और न ही आड़तियों को दलाली! किसानों के इस डर को भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद में बिल्कुल दूर कर दिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य हर हालत में मिलेगा। बावजूद इसके कुछ लोग किसानों तक उनका हक नहीं पहुंचने देना चाह रहे।

किसानों को समझना होगा कि सरकार जो काम करती है, उसमें समाज की भलाई छिपी होती है। किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं होता। अभी सरकार ने जो कानून बनाया है, वह किसानों को समृद्ध बनाने का काम करेगा। किसानों को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग कानून रद्द कराने आंदोलन का सहारा लिए हैं, मगर उन्हें अपनी जिद छोड़नी चाहिए, ताकि अन्नदाता को उसका हक मिल सके। सरकार लगातार कह रही है कि वह बात करने को तैयार है, मगर कानून रद्द कराने की जिद पकड़े कुछ लोग अब पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं।

ट्विटर

डीडीसी चुनाव में भाजपा को मिली जीत लोकतंत्र की जीत है। यह कश्मीर के भविष्य की सोच की जीत है। हम कह सकते हैं कि घाटी में कमल खिल गया है।

रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री

गुपकार गैंग में बहुत से दल इकट्ठा होकर भी भाजपा और मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए हैं। भाजपा को जम्मू कश्मीर में 74 सीटें मिलीं जो कि सबसे ज्यादा हैं।

अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री

सत्यार्थ

सिर्फ कर्म ही सहायक

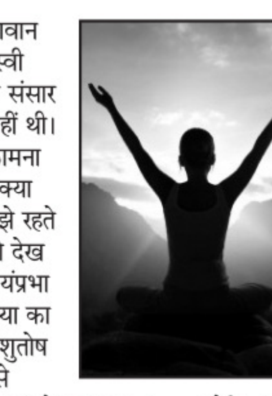

मंकणक की आस्था भगवान सदाशिव में थी। उत्कृष्ट तपस्वी होने के बावजूद उनके मन से संसार और सांसारिकता अभी गई नहीं थी। धन, यश व पुत्र आदि की कामना उनके मन को घेरे रहती थी। क्या करें, इसी उधेड़बुन में वे उलझे रहते थे। उनकी इस मनःस्थिति को देख एक दिन उनकी धर्मपत्नी स्वयंप्रभा ने उनसे कहा- आपकी समस्या का समाधान आपके आराध्य आशुतोष जरूर करेंगे। उन्हीं की कृपा से आपको प्रबोध मिलेगा। मंकणक को यह सुझाव भा गया। उन्होंने भगवान सदाशिव की आराधना आरंभ कर दी। धीरे-धीरे उनका मन भोलेनाथ के चरणों में एकाग्र होने लगा। अंततः वैशाख शुक्ल द्वितीया के चंद्रोदय के साथ भगवान आशुतोष मंकणक के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ कहा-वर मांगो वत्स! मंकणक ने पुत्र की कामना प्रकट की साथ ही अपने लिए धन और यश भी मांगा। इस पर भगवान सदाशिव ने कहा- वत्स, तुमने तपस्या पूर्ण की है व वर प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में भक्ति का अंकुर है। बस, इसी कारण मैं पूछना चाहता हूं कि पुत्र ही किसलिए, पुत्री क्यों नहीं। मंकणक बोले- प्रभु, आगे चलकर पुत्र सहायक बनता है, जबकि पुत्री विदा होकर ससुराल चली जाती है। यह सुन भगवान हंसे और बोले- वत्स, तुमने शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय किया है। तुम्हें यह बोध तो होना ही चाहिए कि सहायक तो मनुष्य के कर्म होते हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष किसी की सहायता नहीं करता। पुत्र हो या पुत्री, उसे संस्कार और शिक्षा प्रदान करके समाज को अर्पित करना माता-पिता का दायित्व है। अपने बच्चों से प्रति-दान की आशा तो पशु-पक्षी भी नहीं करते। यह बातें सुनते ही मंकणक को नई दिशा मिल गई।

कोलकाता में मेट्रो रेल दौड़ाने की तैयारी

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को नोआपारा से दक्षिणेश्वर तक रेलवे ट्रैक पर ट्रायल के तौर पर मेट्रो चलाई गई।

श्रीनगर में बढ़ी ठंड तापमान माइनस पांच डिग्री नीचे

श्रीनगर, (एजेंसी)। कश्मीर घाटी में दिन का तापमान सामान्य रहने के बावजूद रात में हाड कंपाने वाले ठंड से अभी तक कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। श्रीनगर में शून्य से नीचे तापमान जाने से विशेषकर जलाश्य, अधिकतर हिस्सों में नलों में पानी जम गया है।

मौसम विभाग की ओर से कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग में अलग-अलग स्थानों में 27 दिसम्बर को भारी हिमपात होने चेतावनी जारी की गयी है। इसके अलावा हालांकि 26 दिसम्बर को छिटपुट स्थानों पर बारिश या हिमपात होने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित और पाकिस्तान के कब्जे वाले बालटिस्तान में आम तौर पर मौसम शुष्क रहेगा। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आयेगा।

फूलपुर इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस रिसाव से दो मरे, 14 भर्ती

प्रयागराज ■ ब्यूरो

प्रयागराज शहर से लगभग 40 किमी दूर फुलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) में अमोनिया गैस रिसाव होने से काम कर रहे दो लोगों की मौत हो गई जबकि 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इफ्को के पीआरओ विश्वजीत श्रीवास्तव ने बुधवार को यहां कहा कि प्लांट में रिसाव मंगलवार की रात 11.30 बजे हुआ। जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। रात 10 बजे से रात्रिकालीन शिफ्ट में तैनात कर्मी कार्यरत थे। प्लांट में फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। सभी को शहर के एक अस्पताल भेजा गया, जहां असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर अभयनंदन की मौत हो गई। 12 अन्य को शहर स्थित अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रात में काफी कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन जिस स्थान पर गैस का रिसाव हुआ वहां आठ से दस लोग ही थे।मौजूद कर्मचारी बीपी सिंह लीकज को ठीक करने गए, लेकिन गैस की चपेट में आने यह गंभीर रूप से झुलस गए।

योगी ने मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता, घटना की जांच के निर्देश

लखनऊ। उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के फूलपुर स्थित इफको फैक्ट्री में हुइ दुर्घटना के कारणों की जांच करने के साथ मृतक के आश्रितों को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने प्रयागराज में इफको फूलपुर फैक्ट्री में गैस रिसाव से लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश दिए हैं।

दोनो अफसरों ने अपनी जान दे कर लीकेज पर नियंत्रण किया

इफको के दो अधिकारी असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर अभयनंदन तथा ड्यूटी पर तैनात लगभग दो दर्ज़न तकनीशियन यदि अपनी जान की बाजी लगाकर प्लांट में डैमेज कंट्रोल न करते और गैस की आपूर्ति न बंद करते तो यह हादसा एक बड़े इलाके की आपदा में तब्दील हो जाता और फूलपुर इलाके में मिनी भोपाल गैस कांड की पुनरावृत्ति हो जाती।

न्यूज

हाईकोर्ट का भर्ती मामले में रक्षा विभाग से जवाब तलब

श्रीगंगानगर, (एजेंसी)। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एयरमैन भर्ती के एक मामले में रक्षा मंत्रालय के सचिव और केंद्रीय एयरमैन सलेक्शन बोर्ड अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट के अधिवक्ता नवीन शर्मा के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र के नीमला निवासी अजय ने एयरमैन पोस्ट के लिए आवेदन किया था।। लिखित परीक्षा पास करने के बाद उसे मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया गया। मेडिकल परीक्षा के लिए पहले गाजियाबाद और फिर जोधपुर बुलाया गया जहां सेना अस्पताल जोधपुर में विशेषज्ञों द्वारा उसे फिट घोषित किया गया।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मदन लाल का निधन

जम्मू, (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं सांसद मदन लाल शर्मा (68) का निधन हो गया। श्री शर्मा कुछ समय से बीमार थे। उन्होंने रियासी जिले में कटरा स्थित अस्पताल में मंगलवार की देर रात अंतिम सांसे ली। 1983 और 1987 में छांब से दो बार विधायक निर्वाचित हुए श्री शर्मा 1988 में नेकां-कांग्रेस गठबंधन सरकार में मंत्री रहे। वह 2002 में अखनूर से पुनः विधायक निर्वाचित हुए तथा पीडीपी -कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। उन्होंने 2004 में जम्मू पुंछ से लोकसभा चुनाव चुनाव लड़ा और विजयी हुए तथा 2009 में भी अपनी जीत दोहराई।

एटा से लव जेहाद में गायब युवती दिल्ली से बरामद

एटा, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के एटा से जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए अपहरण की गई युवती को पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया। लड़की को एटा के महिला थाना में रखा गया है, उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला चिकित्सालय में मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद लड़की के कोर्ट में बयान दर्ज होंगे। पिछले 17 नवम्बर को एटा के जलेसर से 21 साल की छात्रा को धर्म परिवर्तन और फिर निकाह के लिए किडनेप किया गया था। बाद में दिल्ली में लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह जाविद नामक युवक से करा दिया गया।

भारत ने मध्यम दूरी की मिसाइल का टेस्ट किया

भुवनेश्वर, (एजेंसी)। भारत ने बुधवार को ओडिशा तट से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम) का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से 3.55 बजे एक ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। इस मिसाइल को इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। मिसाइल टेस्ट से पूर्व आईटीआर के 2.5 किमी के दायरे में लगभग 8,100 लोगों को गांवों से स्थानांतरित कर दिया गया था।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे!
कोरोना वायरस से
सावधान रहे
क्योंकि सावधानी
ही बचाव हैं।
कोरोना को धोना हैं।

दो साल में चौथे चुनाव की ओर देश

इजरायल में नेतन्याहू सरकार गिरी, संसद भंग

अगले साल मार्च में हो सकते हैं चौथे आम चुनाव

येरुशलेम ■ एजेंसी

इजरायल की नेतन्याहू सरकार पर एक बार फिर संकट गहरा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार बजट पारित करने में कामयाब नहीं रही जिसके बाद मंगलवार को सरकार गिर गई।

इसी बीच संसद को भंग कर दिया गया है। इजरायल में महज दो साल में चौथी बार हुआ है कि जब देश आम चुनाव के करीब पहुंच गया है। दरअसल, गठबंधन सरकार के सहयोगी और रक्षामंत्री बेनी गांट्ज ने नेतन्याहू पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल में चौथे आम चुनाव अगले साल मार्च में हो सकते हैं।

2 साल से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है इजरायल

बता दें कि इजरायल में 2009 से लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद पर हैं। नेतन्याहू इजरायल में सबसे लम्बे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति भी हैं। लेकिन पिछले 2 साल से इजरायल में राजनीतिक संकट जारी है। दरअसल, इजरायल में अप्रैल 2019 में विधायी चुनाव हुए थे, जिसमें नेतन्याहू के सामने एक नए प्रतिद्वंदी थे, ब्लू एंड वाइट पार्टी के बैनी गांट्ज। इनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य तथाकथित रूप से भ्रष्ट नेतन्याहू को सत्ता से हटाना था।

इसलिए करना पड़ा बार बार चुनाव का सामना

बैनी गांट्ज की पार्टी ने चुनाव में बहुत कम समय में ही 35 सीटें प्राप्त कर लीं, जो की नेतन्याहू की पार्टी के बराबर थी। अप्रैल 2019 के चुनावों का नतीजा ये रहा कि दोनों पार्टियों को 35-35 सीटें मिली। कोई भी पार्टी

बहुमत के लिए जरूरी 60 सीटें प्राप्त नहीं कर सकी और ना कोई गठबंधन सरकार बना सका। इसके बाद इजरायल के राष्ट्रपति ने 17 सितंबर 2019 को पुनः चुनाव कराने की घोषणा कर दी। दोबारा चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 32 सीटें और ब्लू एंड वाइट पार्टी को 33 सीटें मिलीं। इस चुनाव में भी एक बार फिर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी और राष्ट्रपति ने फिर नए चुनाव कि घोषणा कर दी। 2 मार्च 2020 को फिर चुनाव हुए, जिसमें लिकुड को 36 सीटें और ब्लू एंड वाइट को 33 सीटें मिली। इस बार नेतन्याहू को लगा कि वो इस बार सरकार बना लेंगे, लेकिन नहीं बना पाए। राजनीतिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए 16 अप्रैल 2020 को इजरायल के राष्ट्रपति ने संसद के सभी सदस्यों से कह दिया कि या तो वो सरकार बना लें अन्यथा चौथी बार चुनाव होंगे।

रूस के विपक्षी नेता को अंडरवियर के जरिए दिया गया था जहर

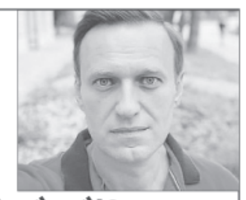

मास्को ■ एजेंसी

रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी सरकार और ब्लादिमिर पुतिन के खिलाफ मुखर रहने वाले सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। हाल ही में वो गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, बाद में पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। अब सीएनएन की एक रिपोर्ट में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये दावा किया गया है कि एलेक्सी नवाल्नी को अंडरवियर में जहर दिया गया था। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि आखिर जहर की भारी डोज के बावजूद वो बच कैसे गए। ये पूरा वाकया इस साल अगस्त का है।

एलेक्सी नवाल्नी कौन हैं?

एलेक्सी नवाल्नी ऐसे विपक्षी नेताओं में से हैं जिन्होंने पुतिन प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया है और वो कई बार जेल भी गए हैं। एलेक्सी नवलनी रूस में राष्ट्रपति चुनाव लड़कर वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुनौती देना चाहते थे और इसके लिए वो पूरे रूस में अपने चुनाव का प्रचार - प्रसार कर रहें थे। नवाल्नी का आरोप है कि रूसी राष्ट्रपति की टीम ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। अब एलेक्सी ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की कि कैसे उन्हें कथित तौर पर (नर्व एजेंट) जहर दिया गया था।

छह महीनों में आव्रजन और शरण प्रतिबंधों में राहत- निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए मौजूदा आव्रजन और शरण प्रतिबंधों में से कई प्रतिबंधों को आगामी छह महीने में हटाए जाने की उम्मीद हैं।

श्री बाइडेन ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में ट्रम्प प्रशासन की कुछ आव्रजन नीतियों को वापस लेने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर कहा, कि इसे लागू करने में छह महीने लग सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वह पहले दिन हर प्रतिबंध को नहीं हटाएगा या तुरंत वर्तमान

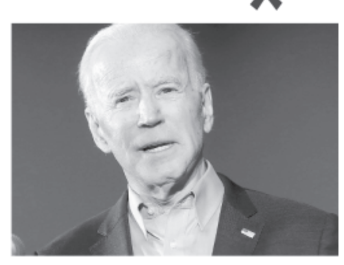

शरण प्रक्रिया को रोक नहीं लगाएगे क्योंकि इससे अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर फंसे 20 लाख प्रभावित होगे। श्री बिडेन ने चीजों को तुरंत बदलने की चेतावनी दी 'यह 20 साल पहले क्या था' केवल संकट को जटिल करेगा।

निश्चित समय में हम वास्तव में बदतर नहीं बेहतर बनाएं

उन्होंने कहा कि मैंने पहले से ही मैक्सिको के राष्ट्रपति और लैटिन अमेरिका में हमारे दोस्तों के साथ मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर दी है तथा निश्चित समय में हम वास्तव में इसे और बदतर नहीं बेहतर बनाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए फंड की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि श्री बाइडेन ने अपने चुनाव अभियान में कहा कि वह अपने शासन के पहले 100 दिनों में ट्रम्प की कई आव्रजन नीतियों को रद्द कर देंगे, इनमें शरण चाहने वालों पर लगे प्रतिबंध भी शामिल है।

नौ माह बाद ईएमयू ट्रेनों में सफर की इजाजत

चेन्नई, (एजेंसी)। दक्षिण रेलवे ने नौ महीने के अंतराल के बाद बुधवार से आम लोगों को चेन्नई उपनगरीय ईएमयू ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत दे दी। लोग अब सामान्य समय में यह यात्रा कर सकेंगे।

रेलवे की घोषणा के मुताबिक सामान्य यात्रियों ने चेन्नई बीच-तंबरम, चेन्नई बीच-चेंगलपट्ट और कांचीपुरम / तिरुमलपुर क्षेत्रों तथा चेन्नई मूर मार्केट-अरकोनम और चेन्नई मूर मार्केट-गुम्मिदिपून्दी खंड पर यात्रा का आनंद लिया। रेलवे के मुताबिक सामान्य समय दिन के शुरूआती समय से सुबह सात बजे तक, साढ़े नौ बजे से साढ़े चार बजे तक तथा पांच बजे से ट्रेनों के बंद होने तक रहेगा। इनके बीच का समय यानि सात बजे से साढ़े नौ बजे और साढ़े चार बजे से सात बजे तक का समय व्यस्त समय होगा। इस समयों के बीच यात्री सरकार की ओर से जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे।

प्रमुख सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा सेंटर

इसरो और आईआईटी (काशी हिंदू विवि) के बीच मंगलवार को आनलाइन कार्यक्रम में करार हुआ। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन और इसरो की तरफ से सीबीपीओ के निदेशक डॉ. पीवी वेंकटकृष्णन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। श्री जैन ने बताया कि इसरो का यह क्षेत्रीय अकेडमिक सेंटर उप्र, मप्र और छग में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

ट्रक मालिकों को फास्टैग से तीन करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लॉजिस्टिक टेक स्टार्टअप, व्हील्सआई टेक्नोलॉजी ने ट्रक मालिकों के साथ किये गये एक सर्वेक्षण के आधार पर कहा है कि टॉल प्लाजा पर फास्टैग से गलत लेनदेन से ट्रक ऑपरेटरों को प्रतिदिन दो से तीन करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है1

कंपनी ने 5 लाख से अधिक फास्टैग उपयोगकर्ताओं पर किए गए शोध के आधार पर यह दावा किया है। उसका दावा है कि हर चार फास्टैग लेनदेन में से एक गलत होता है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रक मालिक हर दिन अपनी कड़ी मेहनत का कुछ हिस्सा खो देते हैं। इस सर्वेक्षण ने स्टार्टअप को फास्टैग से गलत या दोहरे टोल कटौतियों की स्वचालित पहचान प्रक्रिया और धनवापसी सुविधा विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उसन बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि पहली बार लागू की जा रही इस सुविधा में एआई आधारित स्वचालित पहचान प्रक्रिया शामिल है और उन उपयोगकर्ताओं को स्वतः पैसा वापस कर दिया जाता है जिन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। यह प्रणाली भारत के सभी फास्टैग आधारित टोल प्लाजाओं पर काम करती है। यह तकनीक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आईडीएफसी बैंक के साथ मिलकर विकसित की गई है।

कंगना का ऑफिस तोड़ने वाले कमिश्नर 20 को होंगे पेश

मुंबई, (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स और घर के तोड़-फोड़ केस के सिलसिले में महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को समन भेजा है। चहल को 20 जनवरी से पूर्व आयोग के सामने हाजिरी देनी होगी और यह बताना होगा कि उन्होंने बांद्रा पाली हिल एरिया में बनी कंगना की प्रॉपर्टी को नष्ट करने का निर्णय क्यों लिया।

इकबाल सिंह के निर्देशों के बाद ही कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। हालाँकि बाद में कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई को रोकना पड़ा था लेकिन तब तक अभिनेत्री का काफी नुकसान हो चुका था। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने कंगना के बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से परिपूर्ण माना था। इसके साथ ही बीएमसी का नोटिस रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि यह बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई थी।

अमरावती में एक संतरा किसान ने की खुदकुशी

व्यापारी ने फसल नहीं खरीदी तो किसान ने लगाई फांसी, सदमे में भाई की भी मौत

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के अमरावती में एक संतरा किसान ने खुदकुशी कर ली। परिवार का आरोप है कि संतरे की बोली लगाने वाले व्यापारी ने ऐन वक्त पर फसल लेने से इनकार कर दिया था। जब किसान ने इसका विरोध किया, तो व्यापारी ने उसकी पिटाई कर दी। इससे दुखी किसान ने फांसी लगा ली। इस सदमे से किसान के छोटे भाई को हार्टअटैक आ गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अमरावती पुलिस के मुताबिक, किसान अशोक भूयार ने घर में लगे पंखे से फांसी लगाई थी। परिवार के मुताबिक, आत्महत्या से पहले अशोक ने शिक्षा राज्यमंत्री बच्चू कडू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें मदद की गुहार लगाई गई थी। राज्य से बाहर होने के कारण कडू किसान की मदद नहीं कर सके। आखिरकार उसने मंगलवार को आत्महत्या कर ली।

किसान ने पैसे मांगे, तो व्यापारी और थानेदार ने पीटा

परिवार के मुताबिक, किसान ने संतरे की फसल बेचने के लिए व्यापारी अमीन शेख और गफूर शेख से करार किया था। मंगलवार को अशोक भुयार व्यापारी से पैसे मांगने गया था। लेकिन, व्यापारी ने संतरे की फसल खरीदने से इनकार कर दिया। जब किसान ने इसका विरोध किया, व्यापारी ने उसकी पिटाई कर दी। अशोक ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस से भी की थी। परिवार का आरोप था कि जब किसान पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गया, तो मदद करने की बजाय थानेदार ने भी उसकी पिटाई की। इसके बाद किसान ने आत्महत्या कर ली। अशोक की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन पहुंच जमकर हंगामा किया।

खुशखबरी — कोरोना टीके के पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों के आधार पर किया आकलन

देशी वैक्सीन एक साल तक रह सकती है असरदार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश में बन रहे कोरोना टीके को लेकर एक बेहद अच्छी खबर आ रही है। कोवैक्सिन नामक इस टीके के छह से 12 महीने तक असरदार रहने की संभावना है।

टीके के पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों के आधार पर यह आकलन किया गया है। हालांकि, टीका अभी तीसरे चरण के परीक्षण में है। इसके पूरा होने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। भारत बायोटेक और एनआईवी पुणे द्वारा विकसित किए गए कोवैक्सिन टीके के पहले व दूसरे चरण के परीक्षणों को लेकर साइंस जर्नल मेडीरेक्सीव में शोध पत्र प्रकाशित हुआ है।

इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण में 380 स्वस्थ लोगों पर किए गए परीक्षणों में यह नतीजा निकला कि टीके का मनुष्य की टी सेल मेमोरी रिस्पांस अच्छा है। इसके साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिलाइजिंग एंटीबाडी पैदा हो रही हैं।

वैक्सीन वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए ग्रांड चैलेंज की शुरुआत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ 'कोविन' चैलेंज की शुरुआत करने का एलान किया है। यह चैलेंज कोविड वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क (कोविन) की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसे राष्ट्रीय स्तर पर कोविड वैक्सीन वितरण व्यवस्था के लिए तंत्र को प्रभावी रूप से रोलआउट करने और बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस ग्रांड चैलेंज के विजेताओं को कुल 3.85 करोड़ रुपए तक के उपहार मिलेंगे।

कोविड टीकाकरण कब शुरू करेगी सरकार : राहुल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि दुनिया के कई देशों में कोविड महामारी का कहर रोकने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और अब तक लाखों लोगो को यह टीका लग चुका है लेकिन हमारे यहां इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

श्री गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल किया कि दुनिया में अब तक 23 लाख लोगों को यह टीका लग चुका है इसलिए वह (श्री मोदी) बताएं कि भारत में कोविड के खिलाफ टीकाकरण कब शुरू किया जाएगा। श्री गांधी ने ट्वीट कर श्री मोदी से सवाल किया, दुनिया में अब तक 23 लाख लोगों को कोविड का टीका लग चुका है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध रिश्वत बारे मिली ऑनलाइन शिकायत विजीलैंस द्वारा रिश्वत का पर्चा दर्ज

■ जालंधर/रवि

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने शिकायतकर्ता की मदद करने के एवज़ में रिश्वत की माँग करने वाले सब-इंस्पेक्टर नरिन्दर सिंह (नंबर 1846 / पटियाला) के खिलाफ रिश्वत का मामला दर्ज किया है। यह सब-इंस्पेक्टर पुलिस चौकी, बस स्टैंड राजपुरा, जिला पटियाला में तैनात था। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर नरिन्दर सिंह के विरुद्ध तारीख 12.01.2020 को ब्यूरो को एक ऑनलाइन शिकायत मिली थी जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता अमनदीप सिंह निवासी रणजीत नगर, पटियाला ने ब्यूरो तक पहुँच की और बताया कि सब-इंस्पेक्टर नरिन्दर सिंह ने शिकायतकर्ता की माता और उसके चाचा के विरुद्ध दर्ज एक पुलिस केस में शिकायतकर्ता की मदद करने के बदले पैसों की माँग की थी।

उन्होंने आगे बताया कि दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 के अंतर्गत रिश्वतखोरी का मामला ब्यूरो के थाना पटियाला में दर्ज किया गया है और अगली पड़ताल जारी है।

भोगपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को 100 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल समेत काबू किया

■ भोगपुर/रवि

भोगपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घड़ीबखशा मोड़ पर नाकेबंदी दौरान एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल नंबर पीबी 08 बी ए 0907 बजाज डिस्कवर पर सवार होकर आ रहा है तभी वह पुलिस को देख कर पीछे की तरफ जाने लगा तभी उसको काबू कर उसकी तरफ से एक लिफाफा मिला मौके पर उससे 50 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर उसके घर से भी 50 ग्राम हैरोइन बरामद कर दोषी पर मुकदमा नंबर 21 बी 61/85 एन.डी.पी.एस एक्ट पुलिस डिविजन भोगपुर जालंधर दर्ज किया और उसको अदालत में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड लेकर गहराई से पूछताछ की जाएगी कि वह यह नशा कहां से लाता है और आगे किसको सप्लाई करता है।

कर्मचारियों/पैंशनरों के लिए क्रौनिक सर्टिफिकेट बनाने के अधिकार सिविल सर्जनों को दिए : बलबीर सिद्धू

■ जालंधर/ब्यूरो

पंजाब सरकार ने कर्मचारियों / पैंशनरों को मैडीकल खर्च की प्रति-पूर्ति करने की विधि में राहत देते हुए क्रौनिक सर्टिफिकेट बनाने के अधिकार सिविल सर्जनों को देने के आदेश जारी किये हैं।इस संबंधी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि पहले जारी हिदायतों के अनुसार मैडीकल कॉलेज अमृतसर, फरीदकोट, पटियाला, पी.जी.आई. चण्डीगढ़ और एम्ज़ नई दिल्ली और सरकारी मैडीकल कॉलेज और अस्पताल, सैक्टर 32, चण्डीगढ़ को क्रौनिक बीमारियों सम्बन्धी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मान्यता दी गई थी।

उन्होंने कहा कि मुलाजिमों को यह सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जिस कारण पंजाब सरकार ने यह अधिकार सिविल सर्जनों को भी दिए हैं। स. सिद्धू ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि क्रौनिक बीमारियाँ जैसे कि क्रौनिक रीनल फेलियर, इंसुलिन डीपैंडेंट डायबटीज़ मेलीटस, क्रौनिक गलाउकोमा, हाईपरटैंशन, हाईपोथायरायडोज़्म, डायबटीज़ मेलीटस टाइप -2, हैपेटायटस-बी, हैपेटायटस-सी, हाईपरथाईरोइडिज़्म और हेनूमाटोआईड अर्थरैटिस के सीडीसी (क्रौनिक डीसीज़ सर्टिफिकेट) जिला स्तर अर्थात सिविल सर्जन, कार्यालय में भी जारी किये जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बीमारियों का क्रोनिक सर्टिफिकेट जारी करने हेतु यदि सुपर-स्पैशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जोकि सिविल सर्जन हस्पताल स्तर पर उपलब्ध नहीं है तो मरीज़ को कंसलटेशन लेने और जरुरी टैस्ट करवाने के लिए उच्च सरकारी संस्थानों में भेजा जायेगा।

शिक्षा मंत्री ने किसानों के हक में की भूख हड़ताल, केंद्र सरकार को नए कृषि कानून वापिस लेने की अपील

■ जालंधर/ब्यूरो

पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने विधान सभा क्षेत्र संगरूर में एक दिन की भूख हड़ताल की 7 इस भूख हडताल में इलाके के 200 आढतियों ने भी श्री सिंगला का साथ दिया और किसान यूनियनों की मांगों का समर्थन किया। भूख हड़ताल के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए,श्रीसिंगला ने कहा कि किसानों द्वारा शुरू किया गया यह

संघर्ष अब एक सच्चा जन-आंदोलन बन चुका है और अभियान में लोग जाति, धर्म और पेशे को पीछे छोड़ते हुए अपनी भूमिका निभा रहे है।

श्री सिंगला ने कहा कि पंजाब मेंआढतियों और किसान के बीच नाखून और मांस जैसा अटूट और अवियोज्य रिश्ता है जो सौ सालों से चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस भूख हड़ताल के माध्यम से हम किसान यूनियनों द्वारा की जा रही मांगों का समर्थन करते हैं। शिक्षा मंत्री ने काले कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का शीतकालीन सत्र जल्द बुलाने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि काले कानून भारतीय लोकतंत्र के संघीय ढांचे पर हमला हैं। शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार उन मुद्दों पर कानून बनाने की कोशिश कर रही है जो उसके दायरे में नहीं हैं ताकि वह अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा सके।

उन्होंने कहा कि हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने तीनों कानूनों को खारिज कर दिया था, लेकिन केंद्र को भी इन कानूनों को रद्द करना चाहिए तांकि लोगों के मन में कोई भी शंका हो तो उसका निवारण किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने पंजाब भर के आढतियों पर आयकर विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी की भी कड़ी निंदा की।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन छापों के माध्यम से राज्य के आढतियों को डराना चाहती थी जो इस संघर्ष में अपने किसानों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विभाजनकारी विचारधारा के माध्यम से संघर्ष को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रही थी जिसमें वह बुरी तरह से विफल चुकी है और आयकर विभाग के यह छापे केंद्र सरकार की बौखलाहट का नतीजा हैं। सिंगला ने कहा कि भाजपा की वीभत्स चालें अन्य राज्यों में सफल हो सकती है, लेकिन पंजाबी हिंदुभाजपा की साम्प्रदायिक रणनीति समझता है और लोग उसके बहकावे में नहीं आएँगे। सिंगला ने कहा पंजाब के हर समुदाय के लोग इन काले कानूनों का पहले भी विरोध कर रहे थे और आगे भी डटकर विरोध करेंगे। इस मौके पर जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन रजिंदर राजा, मार्केट कमेटी संगरूर के चेयरमैन अनिल घीचा, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश गाबा, पंजाब स्मॉल इंडस्टरीज कार्पोरेशन के वाइस चेयरमैन महेश कुमार मेशी, डायरेक्टर इनफोटेक पंजाब सतीश कांसल, सीनियर कांग्रेसी नेता अमरजीत सिंह टीटू, जसपाल शर्मा पाली, बलबीर कौर सैनी, विजय गुप्ता, सोमनाथ बांसल मंडी प्रधान संगरूर, बिंदर बांसल, पंजाब कांग्रेस लीगल सैल प्रधान एडवोकेट गुरतेज बांसल, परमिंदर शर्मा समेत कांग्रेसी नेता, आढती एसोसिएशन के प्रतिनिधी व अन्य उपस्थित थे।

पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन ने ओ.पी सोनी का सम्मान किया

■ जालंधर/ब्यूरो

पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन के नेतृत्व में एसोसिएशन के नये चुने गए प्रधान श्री जी.बी.एस. ढिल्लों और कार्यकारी समिति के अधिकारियों और सदस्यों ने आज कोर्ट कंपलैक्स में करवाए गए प्रोग्राम में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, फूड प्रोसेसिंग और स्वतंत्रता संग्रामी कल्याण मंत्री श्री ओ.पी. सोनी का सम्मान किया। बार एसोसिएशन का धन्यवाद करते हुए श्री सोनी ने कहा कि वह उन सभी के बीच उपस्थित होकर खुशी और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने

कहा कि वकील एक शिक्षित पेशेवर जमात है और समाज में एक विशेष ओहदा रखते हैं जो संविधान की किसी भी तरह के उल्लंघन से रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देश में न्याय दिलाने और बेहतर प्रणाली को यकीनी बनाने में वकीलों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री सोनी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को 5 हजार रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया।

जमीन से हवा में मार करने में सक्षम मध्यम रेंज की मिसाइल का सफल परीक्षण, श्रीपद नाइक ने DRDO को दी बधाई

■ पणजी/ब्यूरो

केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने बृहस्पतिवार को जमीन से हवा में मार करने में सक्षम मध्यम रेंज की मिसाइल (एमआरएसएएम) के प्रक्षेपण के लिए बृहस्पतिवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बधाई दी।

भारत ने जमीन से हवा में मार करने में सक्षम मध्यम रेंज की मिसाइल (एमआरएसएएम) का बुधवार को ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया था।

अरुणा चौधरी ने 34 आंगनवाड़ी सुपरवाईज़रों को सौंपे नियुक्ति पत्र

■ जालंधर/ब्यूरो

महिलाओं को रोजगार के मौके मुहैया करवाकर उन्हें अधिक सशक्त बनाने की पहल के अंतर्गत पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने आज 34 आंगनवाड़ी सुपरवाईजऱों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इससे एक महीना पहले भी 362 आंगनवाड़ी सुपरवाईजऱों को नियुक्ति पत्र जारी किये गए थे।

यहाँ आज पंजाब भवन में करवाए गए समागम के दौरान एक्स सर्विसमैन और खेल कोटे में से पदोन्नत इन 34 आंगनवाड़ी सुपरवाईजरों को विभाग में निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हुए श्रीमती अरुणा चौधरी ने कहा कि वर्करों को पदोन्नत कर सुपरवाइजर बनाने से न सिफऱ् विभाग को मज़बूती मिलेगी, बल्कि राज्य की नयी पीढ़ी को पौष्टिक खुराक और स्वस्थ वातावरण देने में मदद के अलावा राज्य में हर वर्ग के लोगों को सरकार की कल्याण योजनाओं संबंधी समयबद्ध जानकारी देने में भी ये सुपरवाइजऱ अहम योगदान देंगी।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने और पंचायती चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक लाख नौकरियाँ सरकारी क्षेत्र में देने का ऐलान किया है, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री के साथ विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती राजी पी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव श्रीमती विमी भुल्लर और डिप्टी डायरैक्टर श्री गुरजिन्दर सिंह मौड़ भी मौजूद थे। श्रीमती अरुणा चौधरी ने महिलाओं को लोक सेवा के लिए राजनीति में आगे आने की अपील की और कहा कि इससे महिलाओं के सशक्तिकरण के मंतव्य से शुरू किये प्रोग्रामों को लागू करने में मदद मिलेगी।कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के उद्देश्य 'घर-घर रोजग़ार मिशन' के अंतर्गत नौजवानों को नौकरियाँ देने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में खाली पद भरे जा रहे हैं।

अजिंक्य रहाणे पर काफी दारोमदार रहेगा। मोहम्मद शमी भी टीम में नहीं है और देखना होगा कि टीम संयोजन कैसा रहता है।

स्पोर्ट्स प्लैनट

शर्मनाक हार से दुखी भारतीय क्रिकेट टीम, गौतम गंभीर ने इस तरह बढ़ाया बल्लेबाजों का मनोबल

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है कि एडीलेड में शर्मनाक हार से भारतीय टीम दुखी होगी लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिये कि पहले टेस्ट के पहले दो सत्र में उसका दबदबा था। भारत ने एडीलेड टेस्ट में पहली पारी में 53 रन की बढत बनाई थी लेकिन आस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में उसे उसके न्यूनतम टेस्ट स्कोर 36 रन पर आउट करके आठ विकेट से जीत दर्ज की। गंभीर ने स्टार स्पोटर्स के शो 'क्रिकेट कनेक्टेड' पर कहा ,'' भारतीय टीम को याद रखना चाहिये कि पहले दो दिन उसका दबदबा था। पहले दो दिन मैच पर उसकी पकड़ थी।'' उन्होंने कहा ,'' एक सत्र को लेकर वे दुखी होंगे लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि अभी तीन टेस्ट मैच खेले

जाने हैं और उनके पास उनका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और कप्तान विराट कोहली नहीं है।'' उन्होंने कहा ,'' अजिंक्य रहाणे पर काफी दारोमदार रहेगा। मोहम्मद शमी भी टीम में नहीं है और देखना होगा कि टीम संयोजन कैसा रहता है।'' इससे पहले गंभीर ने कहा था कि भारत को पांच गेंदबाजों को लेकर उतरना चाहिये और रहाणे को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिये। उन्होंने अंतिम एकादश में केएल राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल को शामिल करने की भी पैरवी की थी।

भारत के खराब प्रदर्शन पर बोले शेन वॉर्न, कहा- MCG पर भारत की धज्जियां उड़ा देगी आस्ट्रेलियाई टीम

■ मेलबर्न/ब्यूरो

महान स्पिनर शेन वॉर्न का मानना है कि एडीलेड टेस्ट में शर्मनाक हार से भारतीय क्रिकेट टीम अभी भी सहमी हुई होगी और आस्ट्रेलियाई टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट में उसकी धज्जियां उड़ा देगी। आस्ट्रेलिया ने भारत को पहले टेस्ट में उसके न्यूनतम टेस्ट स्कोर 36 रन पर समेटने के बाद आठ विकेट से जीत दर्ज की थी। दूसरा मैच शनिवार से होगा जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली नहीं खेलेंगे जो अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण स्वदेश लौट गए हैं। वॉर्न ने 'फॉक्स क्रिकेट' से कहा ,'' मुझे लगता है कि आस्ट्रेलियाई टीम उनकी धज्जियां उड़ा देगी।''

उन्होंने कहा ,'' भारत के पास के एल राहुल जैसे शानदार खिलाड़ी हैं।युवा शुभमन गिल भी टीम में होगा। अजिंक्य रहाणे भी बेहतरीन खिलाड़ी है और हमें पता ही है कि चेतेश्वर पुजारा क्या कर सकता है।'' वॉर्न ने कहा ,'' मोहम्मद शमी का नहीं खेलना भी बड़ा नुकसान है।वह बेहतरीन खिलाड़ी है। मेलबर्न में पिच उसकी गेंदबाजी के अनुकूल भी थी।'' पहले टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम की काफी आलोचना हुई लेकिन वॉर्न का कहना

है कि भारतीय बल्लेबाजों को दोष देने की बजाय आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों की तारीफ की जानी चाहिये।

उन्होंने कहा ,'' मैं आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को श्रेय दूंगा जिन्होंने इतनी उम्दा गेंदबाजी की। चारों गेंदबाज और कैमरन ग्रीन ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया। ये महान गेंदबाज बनते जा रहे हैं।'' उन्होंने कहा ,'' पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क और नाथन लियोन काफी समय से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी तुलना मेरे दौर से गेंदबाजों से होगी। अगर अगले चार या पांच साल ऐसा ही खेलते रहे तो शायद यह आस्ट्रेलिया का अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण होगा।

मुख्यमंत्री द्वारा मोबाइल एप और वैब पोर्टल 'पी.आर. इनसाईट' की शुरूआत

■ जालंधर/रवि

डिजिटल पंजाब के प्रति एक और बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज 'पी.आर. इनसाईट' (लोक संपर्क का झरोखा) नामक मोबाइल एप और वैब पोर्टल की शुरुआत की जिससे फीडबैक का निरीक्षण करने और उसके आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में सुधार लाया जा सकेगा ताकि राज्य में लोक समर्थकीय और अन्य पारदर्शी शासन यकीनी बनाया जा सके। जिक्रयोग्य है कि 'पी.आर. इनसाईट' को सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा विकसित किया गया है ताकि राज्य की सभी खबरें और सोशल मीडिया सामग्री का एक ही प्लेटफार्म और डैशबोर्ड मुहैया करवाया जा सके।

31 अग्रणी खबर एजेंसियों / पोर्टलों को पी.आर. इनसाईट एप और पोर्टल के साथ ऑनलाइन जोड़ा गया है और राज्य के समूह विभागों की खबरें/लेखों को इन न्यूज एजेंसियों से तुरंत ले लिया जाता है। खबरों और सोशल मीडिया सामग्री के एक प्लेटफार्म को बाद में आधुनिक और विचारक अध्ययन टूल्ज के प्रयोग द्वारा जांचा जाता है जिससे सरकार की नीतियों बारे नागरिकों की फीडबैक समझने के साथ-साथ शासन बारे भी नागरिकों की धारणा का पता लग सके।इस मौके पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि यह नई एप/पोर्टल लोगों की फीडबैक की कारगर ढंग से जांच करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी जिससे राज्य सरकार की तरफ से चलाईं जा रहीं लोक समर्थकीय नीतियों और प्रोग्रामों में कमीयों को दूर करने में मदद मिलेगी।इस निराले उद्यम के लिए लोक संपर्क विभाग के शानदार कदम की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 'पी.आर. इनसाईट' एप प्रांतीय प्रशासन को अपने कामकाज में और कुशलता लाने के अलावा नागरिक केंद्रित सेवाएं सुचारू ढंग के साथ मुहैया करवाकर लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने में निश्चित रूप से मददगार साबित होगी। इसी दौरान सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि 'पी.आर. इनसाईट' मोबाइल एप और पोर्टल सरकार को अपनी नीतियाँ और ज्यादा उपयोगी बनाने में सहायक होंगे जिनको विशेष सरोकारों के हल, किसी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए संचार और लोगों तक पहुँच करने के प्रोग्रामों में तबदीली लाने के अलावा सरकार को यह समझने में भी पता लगाएगा कि सम्बन्धित सभी प्रमुख पक्ष उसके प्रोग्रामों और प्रयासों को किस नज़रिए से देखते हैं। यह एप सरकार को सकारात्मक नजरिए वाले प्रोग्रामों के बेहतर अमल की पहचान करने और इनको अन्य पर भी लागू करने, प्रभावशाली प्रदर्शन वाला मॉडल बनाने और व्यापक तौर पर सामाजिक व्यापारिक रणनीति तैयार करने के योग्य बनाएगी। सचिव ने आगे कहा कि बीते साल तक खबरों को एकत्रित करने की प्रक्रिया हाथों से की जाती थी जहाँ सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विशेष टीम प्रकाशित खबरों की क्लिपिंग का अध्ययन करती थी और सरकार के सीनियर अधिकारियों द्वारा गहराई से जांच करने के लिए क्लीपिंग्ज तैयार की जातीं थीं। समझा जा सके कि सरकार के प्रोग्रामों और नीतियों बारे नागरिक कैसे महसूस करते हैं।

सूचना

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पी.एस.पी.सी.एल द्वारा लोगों को सूचित किया जाता है की सब डिवीजन बस्तियां टी 4 जालंधर में नई डबल केबिन गाडी लगाई जा रही है । इस सबंध में किसी भी फर्म ने नई गाडी लगानी है तो वह 7 दिनो के अंदर पी.एस.पी.सी.एल दफ्तर में अपनी कुटेशन दे सकता है ।

– जारी करता, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
इंजीनियर दविंदर सिंह

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.